they have and getting investment clearance for them.

SHRI S. B. CHAVAN: These are the new projects. They were not there in the Eighth Five Year Plan.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: As far as the Eighth Five Year Plan was cocnerned, we have been able to persuade the Finance Minister to give us an additional allocation after the Budget was finalised for the quicker completion of the on-going projects, both in the hydel sector as well as in the thermal sector. But unfortunately, these capacities are not of that magnitude that in the first year or two, we will get very substantial additions, and that is why a renovation and modernisation programme, a programme for improving the plant load factor as well as bringing in limited capacities in the liquid fuel project is very important.

Now, I come to the question of counter guarantees. We have only agreed to give counter guarantees for the eight fast track projects which were initiated earlier and for other projects, it is not the Government's intention to give counter guarantees but to link them up with other kinds of reforms—for example, the linking up with Escrow Accounts, in some cases, with distribution sources and so on.

SHRI S.B. CHAVAN: Now, on the basis of techno-economic viability, you must have given these counter guarantees. I am more on that.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Yes, Sir. In fact, due to these kinds of reasons, the counter guarantees have been delayed for the eight projects. The financial closure for a number of them is yet to come because these things are gone into in very great detail.

SHRI S.B. CHAVAN: I would like to know specifically whether this aspect was considered or not. If it was not on the basis of techno-economic feasibility, then the Government of India will have to shell out the money from its own coffer if the State Governments or the Electricity Boards were to pay.

THE DEPUTY CHAIRMAN: As in the case of Enron.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: The Government of India has to give counter—guarantee and in each case techno-economic clearance. Financial closure which is based on that is a pre-condition.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Satish Agarwal. Mr. Agarwal, I think Question No. 63 is also on the same subject. We will club them together. I will ask Shri Maheshwar Singh to put the next question. Then both the questions can be taken up together.

SHRI SATISH AGARWAL: Madam, not only this question but Question Nos. 63, 70 and 80 are also on the same subject which are very important.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let Shri Maheshwar Singh put this question and then we will discuss both the questions together.

देश में विद्युत संकट

*63. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत उत्पादन का अपार भंडार होते हुए भी देश के प्रमुख स्थानों में विद्युत का अभाव है जिसके फलस्वरूप दिल्ली जैसे शहरों के विशिष्ट क्षेत्रों में भी विद्युत कटौती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो जून माह के दौरान दिल्ली के विशिष्ट/अतिविशिष्ट क्षेत्रों में कितने-कितने घंटे की विद्युत कटौती की गई, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) विद्युत की कमी का मुख्य कारण विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर होना है। अप्रैल-जून, 1997 के दौरान ऊर्जा की कमी और व्यस्ततमकालीन कमी क्रमश 12.1% और 17.9% थी। दिल्ली समेत राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है (नीचे देखिए)। विद्युत की उपलब्धता और मांग के बीच सन्तुलन को बनाये रखने के लिए मई और जून, 1997 के दौरान क्रमिक रूप से विभिन्न बस्तियों में एक घन्टे के लोड सैडींग के कार्यक्रम की दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा घोषणा की गई थी। तथापि कुछ क्षेत्रों को दीर्घावधि की विद्युत कटौती और पारेषण ट्रांसफारमेशन के कारण निम्न बोल्टता और वितरण संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा था।

(ग) विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए सरकार अल्पकालीन और दीर्घ कालीन दोनों प्रकार के उपाय कर रही है। अल्पकालीन उपायों में ये शामिल हैं; (i) संयंत्र भार अनुपात (पी०एल०एफ०) में सुधार करना। (ii) पुराने संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य करना। दीर्घ कालीन उपायों में निम्न शामिल हैं।

— क्षमता अभिवृद्धि।

— मांग संबंधी प्रबंधन और ऊर्जा संर्वद्धन।

— विद्यमान विद्युत उत्पादन क्षमता का विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष विद्युत वाले क्षेत्रों से अन्तक्षेत्रीय विद्युत का अन्तरण करके बेहत्तर सदुपयोग करना।

— पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना।

विवरण-I

अप्रैल 1997 से जून 97 तक विद्युत सप्लाई की वस्तु स्थिति

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%	व्यस्ततम कालीन मांग	व्यस्ततम कालीन उपलब्धता	कमी	%
उत्तरी क्षेत्र								
चण्डीगढ़	235	235	0	0.0	169	169	0	0.0
दिल्ली	3765	3726	39	1.0	2240	2150	90	4.0
हरियाणा	3145	3044	101	3.2	1970	1926	44	2.2
हिमाचल प्रदेश	777	777	0	0.0	661	661	0	0.0
जम्मू कश्मीर	1225	1174	51	4.2	900	005	95	10.6
पंजाब	5595	5568	27	0.5	3951	3951	0	0.0
राजस्थान	4780	4704	76	1.6	2700	2640	60	2.2
उत्तर प्रदेश	10050	8938	1412	13.6	6500	4903	1597	24.6
उ० क्षे०	29872	28166	1706	5.7	17900	16064	1836	10.3
पश्चिमी क्षेत्र								
गुजरात	9975	8829	1146	11.5	6200	5148	1052	17.0
मध्य प्रदेश	8125	6896	1229	15.1	5600	3952	1648	29.4
महाराष्ट्र	16000	14854	1146	7.2	9350	8117	1233	13.2
गोवा	332	332	0	0.0	100	100	0	0.0
प० क्षे०	34432	30911	3521	10.2	20500	16515	3985	19.4
दक्षिणी क्षेत्र								
आंध प्रदेश	9740	8047	1693	17.4	5578	4576	994	17.8
कर्नाटक	6600	4597	2083	31.2	4385	3105	1205	27.5
केरल	2775	2116	659	23.7	1920	1442	478	24.9

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%	व्यस्ततम कालीन मांग	व्यस्ततम कालीन उपलब्धता	कमी	%
तमिल नाडु	9795	8294	1501	15.3	5754	1622	1132	19.7
द० क्षे०	28990	23054	5936	20.5	16500	13354	3226	19.5
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	2300	1843	457	19.9	1710	1047	663	38.8
डी०वी०सी०	2010	1978	32	1.6	1490	1179	311	20.9
उड़ीसा	2635	2572	63	2.4	1900	1636	264	13.9
पश्चिमी बंगाल	4030	3943	87	2.2	2775	2535	240	8.6
पू० क्षे०	10975	10336	639	5.8	7742	6294	1448	18.7
अरूणाचल प्रदेश	39.5	20.4	19.1	48.4	47	40	7	14.9
आसाम	716.9	665.2	51.7	7.2	541	513	28	5.2
मणीपुर	132.3	91.6	40.7	30.8	90	70	20	22.2
मेघालय	94.3	94.3	0.0	0.0	91	91	0	0.0
मिजोरम	54.1	34.2	19.9	36.8	52	43	9	17.3
नागालैंड	57.2	38.9	18.3	32.0	39	37	2	5.1
त्रिपुरा	134.7	96.4	38.3	28.4	96	68	28	29.2
उ० पू० क्षे०	1229.0	1041.0	188.0	15.3	935	848	87	9.3
सारा भारत	105498	92770	12728	12.1	62927	51649	11278	17.9

श्री महेश्वर सिंह: उपसभापति महोदया, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, उसके अंतर्गत केवल मात्र चार प्रांत ऐसे हैं चंडीगढ़, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और गोवा, जो कि अपनी आवश्यकतानुसार बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, बाकी शेष जितने प्रांत हैं वह सब अपनी आवश्यकता से भी कम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, यहां तक कि जम्मू-कश्मीर जैसा पहाड़ी प्रांत और आपके पूर्वोत्तर राज्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि ताप विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली आपके पनबिजली परियोजना से उतपन्न होने वाली बिजली की तुलना में महंगी है और फिर भी आप ताप परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं? तो कौन से ऐसे कारण हैं, जिससे आप जल विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं? दूसरा प्रश्न, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है, क्या यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में है कि पहाड़ों में नदियों के बहते हुए पानी के करण्ट से छोटे-छोटे डैम बनाकर भी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है? इससे न तो कोई भूमि जलमग्न होने की समस्या होती है, न ही लोगों के विस्थापित होने की समस्या होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि कौन-कौन से ऐसे प्रान्त हैं, जिन्होंने इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु आपसे आग्रह किया है और किन-किन परियोजनाओं के लिए आपने धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की है?

श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ: मैडम, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस समय जो बिजली की स्थिति है, वह चिंताजनक है। अगर देश में 12 प्रतिशत की एनर्जी शार्टेज हो और 18 प्रतिशत की पीकिंग शार्टेज हो तो इसके बारे में यह कह देना कि बहुत चीजें ठीक चल रही हैं, यह तो बड़ा गलत है। इस बात पर तो मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। माननीय सदस्य की इस बात पर भी मैं सहमत हूं कि हाइडल प्रोजेक्ट की जो कोस्ट है, हालांकि उसकी कैपिटल कोस्ट काफी बड़ी होती है और क्योंकि उसकी रनिंग कोस्ट कम है तो लेबलाइज कोस्ट थर्मल प्रोजेक्ट, खासकर के जो कोयला क्षेत्रों से परे हों तो, वह ज्यादा है। हम बड़े-बड़े हाइडल प्रोजेक्टस को पूरी प्राथमिकता दे रहे हैं और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें जो विनियम की जरूरत थी, वह जो इंपलीमेंटेशन में है उनमें जैसा मैंने कहा, इस साल हमने वित्त मंत्री से और पैसे लेकर उनके अंदर डाले हैं ताकि फंडस की शार्टेज के कारण जो हाइडल प्रोजेक्ट अभी इंपलीमेंटेशन में है वह न रुके। तीसरी

बात, माननीय सदस्य ने जो कही है, वह बड़ी महत्वपूर्ण है, कि कई ऐसी छोटी योजनाएं हैं। अब इसके बारे में ऐसा है कि एक तो जो बहुत छोटी योजनाएं होती हैं उनको मेरे सहयोगी मंत्री कैप्टेन निषाद जी देखते हैं, लेकिन बहुत सारे स्माल हाइडल प्रोजेक्टस हैं, जो दो किस्म के हैं। एक रन आफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं, जिसमें नदी बह रही है उसके ऊपर कुछ किया जा सकता है। और दूसरा ऐसे जो कैनाल्स में लगाए जा सकते हैं। खास करके मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि कैनाल्स वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जल्दी ऊर्जा मिल सकती है क्योंकि अगर आप एक रेगूलेटर का डिजाइन कर लें तो बाकी उसके डिजाइन रिप्लीकेट किए जा सकते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी ने हमें एक ऐसी ...(**व्यवधान**) अब माननीय सदस्य मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं...(**व्यवधान**)

श्री महेश्वर सिंह: सुन रहा हूं।

श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ: इस समय एक 6300 या 6400 मेगावाट की प्रीफीजिबिलिटी योजना दी है जिसमें कि एक ऐसे प्रोजेक्ट की प्रीफीजिबिलिटी की स्टडी की गयी है— कौन-कौन सी कैनाल्स पर हो रहा है और हो सकता है। तो उसके लिए इस साल हमें जो ज्यादा पैसे मिले हैं, हम उसकी फंडिंग के लिए एक खास प्राविजन कर रहे है और मैं हर एक मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि आपके प्रदेश में ये योजनाएं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी ने आइडेंटीफाई की है— छोटी योजनाएं। इसके लिए अगर आप लोन असिस्टेंस चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रावधान मिनिस्ट्री आफ पावर के बजट में पावर फाइनेंस कारपोरेशन के माध्यम से हम करेंगे। तो इसीलिए मैं इस बात को काफी प्राथमिकता देता हूं क्योंकि मैं मानता हूं। इस साल और अगले साल हम ऐसी योजनाओं को— जैसे कि विंड पावर की योजना है, कर्नाटक में अभी एक 400 मेगावाट का प्राजेक्ट था जो अटका हुआ था, उसको बैंक गारंटी चाहिए थी तो मैंने पावर फाइनेंस कारपोरेशन से कहा कि जल्दी उसका काम करें— या ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। उसके लिए प्रावधान भी कर रहे है और उनका आइडेंटीफिकेशन भी हो चुका है मैं माननीय सदस्य को सी०ई०ए० की रिपोर्ट की वह कापी आज भिजवा दूंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is this an alternate source of energy?

SHRI YOGINDER K. ALAGH: This is a very specific thing. These are small hydel power projects.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you thinking of an alternate source of energy?

SHRI YOGINDER K. ALAGH: We break them up into wind power and hydel power. There is a specific strategy and funding for each one of them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think I am also supplementing something.

श्री महेश्वर सिंह: महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस समय देश का बिजली का कुल उत्पादन कितना है और आवश्यकता कितनी है? सन् 2000 तक हमारी आवश्यकता क्या हो जाएगी और उसके मुताबिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने क्या योजना बनाई है? दूसरा, महोदया, जैसा कि आपको विदित ही है पहाड़ों को प्रकृति ने ऐसा पानी दिया है जिससे बिजली पैदा हो सकती है, हमें पत्थर ऐसा दिया है जिससे सीमेंट बन सकता है, सौन्दर्य ऐसा दिया है कि देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग उसको देखने आते हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि क्या आप इस बात से अवगत हैं कि हिमांचल 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले तीन वर्षों में कितनी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आपको दी और किन-किन परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों में आपने धन उपलब्ध करवाया है?

श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ: जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इस समय भारत में 12 प्रतिशत की ऊर्जा का घाटा है और हमारा उद्देश्य यह है कि इस बार....

श्री महेश्वर सिंह: मेगावाट में बताइए कि अभी कितना आपका उत्पादन है और कितनी आपकी आवश्यकता है?

श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ: अब यूनिट्स की बात करूं या मेगावाट की बात करूं। उसमें क्यों ज्यादा समय बिताना चाहते हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Actually, Mr. Minister, you are an economist. You can go by percentages.

They are Members of parliament. They go by other figures.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: No dobut I am an economist. Our target for this year is to generate 425 billion units of power ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not units, tell us in megawatts. Now I will need a calculator to tell them ...*(Interruptions)*...

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Converting this into megawatts will not be proper. I happen to be an economist. So, I think it will be a very imprecise answer.

Energy flow, capacity, is like a stock. Supposing I have the capacity and it is not used then it does answer the hon. Member's question. As far as the Plan period is concerned, the intention is ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think his question is specific. He is asking you what the capative power is. He is asking you what plans you have, what the production at the moment is, what the requirement along with your captive power is an how you are going to improve?

SHRI YOGINDER K. ALAGH: There is no captive power in my answer at all. the plain fact of the matter is, if we generate 429 billion units of energy this year which is our target, which would be at a reasonable level of plant load factor of the existing capacity of around 85,000 MW, then we would be having a very small energy and peak deficit at the end of the year because going from production of energy of a MW, one has to make an assumption of capacity use otherwise, one would be making a technical error. In the short run deficits should be in energy and not in megawatts. Madam, I do not want to take your time on this but please take my word for it. Now the other question is, there is one demand that has been estimated, which is around 53,000 MW additional. At present we see around 40,000 MW if we push very hard in the Ninth Plan. I set up another task force as soon as I joined the Ministry—as the Power Secretary has announced—where we are asking our people to identify another 10,000 MW of capacity. I have handled the funding question earlier. I would not like to plan for an energy shortage at the end of the Ninth Plan, by the year 2002. But these figures will only be firmed up by November because they have to be discussed with the Planning Commission.

श्री महेश्वर सिंह: महोदया, मेरे सवाल के "बी" पार्ट का जवाब नहीं आया कि क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत है कि हिमाचल प्रदेश अकेला 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है और आपको कितनी परियोजनाएं उन्होंने यहां भेजी हैं ताकि आप आर्थिक सहायता प्रदान करें और कितनी परियोजनाओं को गत तीन वर्षों में आपने आर्थिक सहायता प्रदान की है?

श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ: महोदया, हिमाचल प्रदेश में जो हाइडल के केन्द्रीय प्रोजेक्ट्स है उनमें जितना भी पैसा उनको इस में चाहिए था, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि वह हमने प्रावधान किया है। दूसरी बात यह है कि हम हरेक सी०एम० साहब से यह लिख रहे हैं कि देखिए, जो हमको दो सौ, तीन सौ करोड़ रुपये की इन्टेस्ट सबसिडी मिली है उससे हम 10—12 हजार करोड़ रुपये का पैसा लीवरेज करना चाहते हैं क्योंकि राज्य सरकार को हम यह कहना चाहते हैं कि आप इसका फायदा उठाएं और हिमाचल प्रदेश में जो राज्य सरकार के प्रोजैक्ट्स हैं उसमें हमने उनको लिखा है, और भी राज्यों को लिख रहे हैं, तो इससे प्रावधान किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि निजी क्षेत्र में भी हाइडल प्रोजैक्ट्स के लिए पालिसी एनाउंस हो चुकी है, टैरिफ शैड्यूल एनाउंस हो चुके हैं और वह भी एनकरेज की जायेगी।

SHRI SATISH AGARWAL: The hon. Minister must be well aware and is well aware that electricity is one item which cannot be stored. So if you generate electricity and there are no transmission lines, then it is useless. It is a false promise. May I know from you whether public sector will occupy commanding heights so far as construction of

transmission lines is concerned? If it so—as stated by you in answere to your question No. 70, which is far ahead, seven steps ahead—what is the addition so far as transmission lines are concerned in this country? How much have you added, how much do you intend to add because I know Dabhol power project has been approved? That is Naphtha-based. Out of 79 Nephtha-based projects, Rajasthan has got nine, Dabhol is one of them. But when generation takes place, there are not transmission lines from Dabhol. So the generation is useless, the project becomes useless. What have you done and what do you intend to do so far as construction of transmission lines by the public sector is concerned?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the Industry Minister should answer that question.

SHRI SATISH AGARWAL: No, no, he has stated in his answer that he is responsible for the public sector. So I want to know it.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Madam, I would like to assure the hon. member, through you, that we are giving priority to public sector investment in transmission, particularly in HVDC lines. Now, our target at present for the Ninth Plan is being put up in terms of 3,878 circuit kilometres for HVDC of the national sector and 34,577 of 400 KVA...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH AGARWAL: I did not ask about the Ninth Plan.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: About this year?

SHRI SATISH AGARWAL: About this year and last year. I wanted to know how much you added in the transmission lines in the public sector and how much investment you made for that purpose.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: For example, at present we have completed a major evacuation link of 400 KVA between Maharashtra and Andhra Pradesh. It is being charged right now. You may recall that at the end of May this year, a 400 KVA line to Delhi was inauagurated by the Chief Minister, Sahib Singhji. Of course, we have not been able to bring power to Delhi because the Delhi Vidyut Board has still to prepare the gantry. Agarwalji, don't shake you head. I am answering your specific question. Let me know if you want specific answers from me. You cannot shake your head when I am giving you specific replies.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no prohibition on shaking head. It can be for 'yes' or 'no'.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Madam, I am trying to satisfy him by giving specific replies. I am giving specific large projects which link power-surplus regions with power-deficit regions. We are giving high priority to link the eastern region with the southern region for off-peak power; to link the western region with the sourthern region; to link the northern region's surplus areas with those where there are deficits. These are specific projects which were delayed by 2-3 months. We are trying to see to it that we brought them, charged them and got them going.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Urmilaben Chimanbhai Patel. She can throw more light because she was a former Power Minister. I hope she had the power to throw light.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Madam, the hon. Power Minister has stated that the Government has permitted the private sector to produce fuel-oil-based power. I would like to know whether it is a fact that IPCL has offered to establish in Gujarat ten power projects within 1½ years using residual oil and that the State Government has not shown any interest. I would like to know whether the Gujarat Chief Minister did not find it lucrative. The company was said to be prepared to sell the power produced by it at the existing rates. The second part of my question is ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister answer the first question because we don't have the time.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: the second part of my question is whether it is a fact that the respected Power Minister has planned to have a joint venture power project in collaboration with the Gujarat government and the NTPC at Simhadri in Andhra Pradesh and Faridabad in Haryana. I would like to know the States which are going to be benefited by them and the share of the respective States, particularly of Gujarat.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Madam, as a matter of policy, we have permitted the oil companies to use their residual fuels for power generation. But I am not aware, right now, of any proposal by the IPCL. I would have to check on that.

The hon. Member is absolutely right that we have sanctioned two State-level projects—one at Simhadri in Andhra Pradesh and the other at Faridabad in Haryana. If the State Governments have specific proposals to make to the NTPC *regarding such projects either as joint* ventures or with different financial arrangements, we would encourage the NTPC to examine them. Now, NTPC is an autonomous *navratna* and we will encourage it to examine such proposals.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, we have discussed a lot about the supply side. But no power crisis or problem in a developing country can be sorted out without some type of demand management. In his answer to this question, the hon. Minister has mentioned about the demand management. Now, there is a lot of confusion about 'shortage of the peakload' and 'shortage of baseload'. The main point is the peakload. So, I would like to know from the hon. Minister what steps are being taken by the Government specifically for peakload chopping as a part off demand-side management.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Madam, it will require a very long answer because in it is involved the whole question of financial reforms at the State level, the question of appropriate pricing policy...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I am asking about the peakload chopping. this is noting financial, this is basically a technical point, the demand side management. What type of demand management is the government thinking of?

SHRI YOGINDER K. ALAGH: The hon. Member knows that three States—Kerala, West Bengal and I think Tamil Nadu—already have a principle of 'Time of the Day' meterage, which means at the peak hour they charge higher and, therefore, encourage industries to flatten the load curve. These policies where one gets into the economic cost of energy and also in its regional and 'Time of the Day' variations, are the main thrust of answering his question also because now that in many States it is the household sector which accounts for the peak in the evening, there are a number of other management measures like more efficient bulbs and tubelights and things of that kind and household equipment which will help solve the problem. In fact, in the Bill on the Energy Conservation Authority that we will be bringing before the Parliament, I hope that we will be able to persuade the housewives also to work with us in solving this problem.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Actually, there should be a national power grid between the North-East and the furthermost point in the west because there is a time-difference in the sunrise and the sunset.

दवे जी, आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मैडम, मैं सीधा सवाल ही करूंगा माननीय मंत्री जी से, कि सरकार के पास कोयले वाली बात आई, हाइडल वाली बात आई, लेकिन टाइडल वेव्ज के लिए कई जगह सर्वे हो चुकी है, कच्छ में भी यह सर्वे हो चुकी है, यह प्रोजेक्ट

बाइबल भी है और देश में इलेक्ट्रिसिटी की कमी भी है, तो क्या सरकार इस कमी की पूर्ति करने के लिए टाइडल वेव्ज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देश को देने के बारे में सोचेगी?

श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ: मेरी तो नोन कन्वेन्शल एनर्जी से बहुत सहानुभूति है। मैं तो माननीय सदस्य से कहूंगा, उनको राय दूंगा कि वह मेरे सहयोगी मंत्री कैप्टेन निषाद से यह सवाल पूछें।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think this question of power generation is very important and if the members so feel...

SHRI SATISH AGARWAL: There should be a healf-an-Hour Discussion on this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have taken more than half-an-hour on it today in the question Hour. But you cannot discuss the entire power crisis—I don't mean the political power, I mean the electricity—in the country. We should have a full-fledged discussion on it. If the Members so agree, we can discuss it in the Business Advisory Committe.

SHRI SATISH AGARWAL: Yes, Madam, we should have a discussion.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: I would be very happy, Madam, for a full discussion because that would support...

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, we will discuss it today in the Business Advisory Committee and in the next week perhaps...

SHRI SATISH AGARWAL: It would be more advisable if the Minister gives us the last position with regard to power and if that paper is circulated to the Members, it will become a very structured debate. You can give a working paper on the power scenario.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: We will be very happy to circulate a very detailed paper for such a discussion.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I want to know whether it will be discussed through a Short Duration Discussion or a Calling Attention Montion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whichever way we decide; but I think there should be a full-fledged discussion because living in Delhi if we are thrown into darkness, at least you can throw some light even with a candle.

Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

गेहूं की खुली बिक्री पर सरकार द्वारा प्रतिबंध

*64. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और प्रतिबंध की अवधि क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गेहूं की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी भारतीय खाद्य निगम व्यापारियों को गेहूं बेच रहा है;

(घ) यदि हां, तो निगम के किस गोदाम से कब-कब कितना गेहूं बेचा गया और इस अवैध बिक्री से भारतीय खाद्य निगम को कितने रुपये का घाटा हुआ; और

(ङ) प्रतिबंध के बावजूद गेहूं बेचने में लगे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इस घाटे को सरकार किस प्रकार पूरा करेगी?

खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पूल में गेहूं का कम स्टाक होने के कारण खुले बाजार में बिक्री योजना पहली अप्रैल, 1997 से अगले आदेश होने तक समाप्त कर दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।